

**प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार की अध्यक्षता में दिनांक 30.06.2017 को राज्य के नगर पंचायतों के कार्यपालक पदाधिकारी के साथ हुई विभिन्न योजनाओं की समीक्षा बैठक की कार्यवाही**

**उपस्थिति— उपस्थिति पंजी के अनुसार।**

2. **सबके लिए आवास योजना—** नगर पंचायतों में इस योजना की प्रगति बहुत ही खराब है। बरौली, बिक्रमगंज, दिघवारा, एकमा बाजार, खड़गपुर, कोवाथ, मोहनिया, नौवतपुर, महुआ, मनेर, कटैया, राम नगर नगर पंचायतों की प्रगति शून्य है। सभी संबंधित कार्यपालक पदाधिकारी जुलाई, 17 के अंत तक प्रगति लायें। श्री एन.के. सिंह, अपर सचिव प्रगति की सतत समीक्षा करें। संतोषजनक प्रगति नहीं होने पर कार्यपालक पदाधिकारी के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई किया जाय। कई नगर पंचायतों से MIS पर प्रतिदिन प्रगति प्रतिवेदन नहीं भेजा जाता है। साथ ही मोबाईल रजिस्ट्रेशन, लाभुकों का आधार कार्ड से संबद्धीकरण नहीं किया गया है। इसे शीघ्र निष्पादित करा लिया जाय। साथ ही नियमित रूप से प्रगति प्रतिवेदन भेजना सुनिश्चित किया जाय। कार्यालय आदेश निर्गत हो जाने के उपरांत प्रथम किश्त का भुगतान शीघ्र किया जाय। जिनके द्वारा प्रथम किश्त का उपयोग कर लिया गया उन्हें द्वितीय किश्त का भुगतान किया जाय। जहाँ राशि की कमी है वे उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ राशि की माँग कर सकते हैं। जिन लाभुकों के पक्ष में एल.पी.सी निर्गत नहीं हो पा रहा है वहाँ अंचल अधिकारी से मिलकर एल.पी.सी. निर्गत कराने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाय। जिन नगर पंचायतों के कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा इस योजना में निर्धारित लक्ष्य प्राप्त किया जाना संभव नहीं है/ जमीन की अनुपलब्धता है उन नगर पंचायतों के कार्यपालक पदाधिकारी बोर्ड की बैठक में प्रस्ताव पारित कराकर इस योजना में दी गई राशि को प्रत्यर्पित कर सकते हैं।

बरवीघा, जगदीशपुर, शेरघाटी, रिविलगंज, मखदुमपुर के कार्यपालक पदाधिकारियों द्वारा आई.सी.आई.सी.आई. में खोले गये खाते के संचालन में कठिनाई हो रही है। आई.सी.आई.सी.आई. के प्रतिनिधियों को इस संबंध में शीघ्र कार्रवाई करने हेतु निदेशित किया गया। सभी कार्यपालक पदाधिकारी राजीव नगर स्थित NIC के कार्यालय में जाकर PFMS में DSC का पंजीकरण करा लें।

**(अनुपालन—सभी नगर पंचायतों के कार्यपालक पदाधिकारी/  
श्री एन.के. सिंह., अपर सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग)**

3. **शौचालय निर्माण** — शौचालय निर्माण कार्य में गति लाया जाय। जिन नगर निकायों में लाभार्थियों का चयन किया जा चुका है, उन्हें प्रथम किश्त का भुगतान किया जाय। अब तक जितने भी शौचालय का निर्माण पूरा हो चुका है तथा जितने में कार्य किया जा रहा है उसकी संख्या एवं अद्यतन फोटो SBM के पोर्टल पर ऑनलाईन अपलोड कराकर प्रतिवेदन MIS के माध्यम से भेजें ताकि इसका सतत अनुश्रवण किया जा सके। ODF प्राप्ति हेतु सभी शहरों में शीघ्र IHHL, Community Toilets एवं Mobile Toilets का निर्माण कराया जाए।

**(अनुपालन—सभी नगर पंचायतों के कार्यपालक पदाधिकारी)**

4. **DAY NULM** — नगर पंचायत, लालगंज में नाईट शेल्टर के निर्माण हेतु काम चल रहा है तथा प्रथम किश्त का भुगतान कर दिया गया है। नवम्बर, 17 तक कार्य पूरा हो जाएगा। हवेली खड़गपुर में पुनर्निविदा निकाली जा रही है। राजगीर एवं झांझा में जमीन की समस्या थी जिसे निष्पादित कर लिया गया है निविदा निकालने





की प्रक्रिया प्रारंभ है। वारसलिंगंज की निविदा निष्पादित कर कार्य आवंटन पत्र निर्गत किया जा चुका है। नवगछिया के रैन वसेरा के निविदा के संबंध में यंत्र-संयंत्र का भौतिक सत्यापन कर प्रतिवेदन भेजने का निदेश दिया गया जो अद्यतन अप्राप्त है। City Vendor के लिए कौशल प्रशिक्षण हेतु आई कार्ड निर्गत किया जाय।

**(अनुपालन-सभी नगर पंचायतों के कार्यपालक पदाधिकारी)**

5. **नल-जल योजना**— कोचस एवं चकिया में इस योजना की प्रगति शून्य है। सभी निकाय अपने सभी वार्डों में योजना का प्राक्कलन तैयार कर जुलाई माह के अंत तक निविदा प्रकाशित करना सुनिश्चित करें। जहाँ निविदा की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है वहाँ कार्यादेश निर्गत कर कार्य प्रारंभ कराया जाय। विभाग में CS के लिए आये हुए प्रस्तावों का निष्पादन शीघ्र किया जाय। बिहार राज्य जल पर्षद द्वारा हो रहे कार्य का भी सतत् समीक्षा किया जाय। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के अधीन वाले क्षेत्रों का सर्वे कराकर/जाँच कर (जल की गुणवत्ता को जाँच कर) पूर्व में दिये गए निर्देशों के अनुसार टेक ओवर कर लिया जाय।

**(अनुपालन-सभी नगर पंचायतों के कार्यपालक पदाधिकारी)**

6. **13<sup>th</sup> Finance** — 13<sup>th</sup> Finance में उपलब्ध करायी गयी राशि को जुलाई माह के अंत तक व्यय कर / समायोजन कर विभाग में अद्यतन प्रतिवेदन भेजना सुनिश्चित किया जाय।

**(अनुपालन-सभी नगर पंचायतों के कार्यपालक पदाधिकारी)**

7. **सम्राट अशोक भवन (प्रशासनिक भवन/नगर सरकार भवन)**— सम्राट अशोक भवन/ प्रशासनिक भवन के निर्माण हेतु शीघ्र जमीन का चयन कर अग्रेतर कार्रवाई की जाय। जमीन उपलब्ध हो जाने पर निविदा का प्रकाशन शीघ्र किया जाय। जहाँ कार्य प्रारंभ है उसकी सतत् समीक्षा की जाय। जमीन अनुपलब्धता की स्थिति में राशि वापस कर दी जाय। ससमय प्रगति प्रतिवेदन भेजना सुनिश्चित किया जाय।

**(अनुपालन-सभी नगर पंचायतों के कार्यपालक पदाधिकारी)**

8. **मुख्यमंत्री शहरी नली-गली पक्कीकरण निश्चय योजना**— योजना का सप्ताहिक प्रगति प्रतिवेदन भेजना सुनिश्चित किया जाय।

**(अनुपालन-सभी नगर पंचायतों के कार्यपालक पदाधिकारी)**

9. **उपयोगिता प्रमाण-पत्र/ऑडिट रिपोर्ट से संबंधित लंबित मामले**— उपयोगिता प्रमाण-पत्र विभाग को शीघ्र भेजें। ऑडिट रिपोर्ट से संबंधित मामले का निष्पादन जुलाई, 17 तक करना सुनिश्चित किया जाय। नगर पंचायतों में लंबित मामले की सूची वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। निष्पादित मामलों को साक्ष्य के साथ महालेखाकार, बिहार, पटना को भेजते हुए एक प्रति विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

**(अनुपालन-सभी नगर पंचायतों के कार्यपालक पदाधिकारी)**

10. गोगरी जमालपुर, अरेराज, मरौढ़ा, मोतीपुर, मुरलीगंज नवीनगर, टेकारी एवं विक्रम नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी बैठक में अनुपस्थित हैं। बहादुरगंज, बख्तियारपुर, बनमनखी, बिहिया, दलसिंह सराय, कोचस, मनेर एवं मीरगंज नगर पंचायत से बैठक में लिपिक/प्रधान लिपिक/लेखा लिपिक द्वारा भाग लिया





पंचायतों के कार्यपालक पदाधिकारी से बैठक में भाग नहीं लेने के संबंध में स्पष्टीकरण पूछा जाय एवं स्पष्टीकरण के निष्पादन तक वेतन स्थगित रखा जाय।

(अनुपालन— निदेशक, नगरपालिका प्रशासन।)

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

*Signature*

*Signature*

*Signature*  
7/7/2017

(चैतन्य प्रसाद)

प्रधान सचिव

नगर विकास एवं आवास विभाग

बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 10/07/2017

*Signature*

7/7/2017

प्रधान सचिव

पटना, दिनांक 10/07/2017

ज्ञापांक 4530 / न0वि0एवंआ0 विभाग /  
प्रतिलिपि— माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

ज्ञापांक 4530 / न0वि0एवंआ0 विभाग /  
प्रतिलिपि— सभी नगर पंचायतों के कार्यपालक पदाधिकारी / विभाग के सभी संबंधित पदाधिकारी / प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव / आई0टी0 मैनेजर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

*Signature*

*Signature*  
7/7/2017  
प्रधान सचिव